



गरीबी उन्मूलन में ग्रामीण अवसंरचना की भूमिका: बीकानेर-हनुमानगढ़ का तुलनात्मक विश्लेषण

महेंद्र सिंह¹

¹ शोधार्थी, विभाग - अर्थशास्त्र, श्री खुशालदास विश्वविद्यालय, पीलीबंगा, हनुमानगढ़.

ABSTRACT:

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था सामाजिक-आर्थिक विकास की आधारभूमि है। ग्रामीण अवसंरचना-सड़क, बिजली, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसे संसाधनों का मजबूत तंत्र-न केवल जीवन-स्तर को बेहतर बनाता है, बल्कि ग्रामीण जनसंख्या को आय के अवसर, बाजार तक पहुँच और सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। यह शोध पत्र राजस्थान के दो जिलों-बीकानेर और हनुमानगढ़-का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि अवसंरचनात्मक विकास में हुए अंतर ने दोनों जिलों में गरीबी उन्मूलन की दिशा में क्या प्रभाव डाले। अध्ययन दर्शाता है कि जहाँ हनुमानगढ़ सिंचाई और कृषि अवसंरचना में अग्रणी रहा है, वहीं बीकानेर में जल-संकट, मरुस्थलीय भौगोलिक स्थिति और सीमित कृषि-योग्यता ने ग्रामीण जीवन को अधिक चुनौतीपूर्ण बनाया है। परिणामस्वरूप दोनों जिलों में गरीबी उन्मूलन की गतिशीलता अलग-अलग दिशाओं में विकसित हुई है।

KEYWORDS:

ग्रामीण अवसंरचना, गरीबी उन्मूलन, बीकानेर, हनुमानगढ़, सिंचाई, परिवहन, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तुलनात्मक अध्ययन।

PAPER ACCEPTED DATE:

13th December 2025

PAPER PUBLISHED DATE:

15th December 2025

PAPER DOI NO:

10.5281/zenodo.17939534

PAPER DOI LINK:

<https://zenodo.org/records/17939534>

प्रस्तावना -

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उसके ग्रामीण विकास की मजबूती पर निर्भर करती है, विशेषतः भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में। ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना केवल भौतिक संसाधन नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा आधार है जो सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर और विकास के समान वितरण को सुनिश्चित करता है। राजस्थान, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान, प्राकृतिक परिस्थितियों और संसाधन वितरण की असमानता के कारण ग्रामीण विकास की चुनौतियों से जूझता रहा है। इस संदर्भ में बीकानेर और हनुमानगढ़ दो ऐसे जिले हैं जो भौगोलिक, ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टि से परस्पर भिन्न हैं, किन्तु दोनों ही अपने-अपने ग्रामीण विकास के मॉडल में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि ग्रामीण अवसंरचना की स्थिति और उसकी उपलब्धता ने इन दोनों जिलों में गरीबी उन्मूलन पर किस प्रकार प्रभाव डाला है। अध्ययन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क संपर्क, ऊर्जा, उद्योग और सामाजिक संरचनाओं को केंद्र में रखा गया है।

भौगोलिक और प्राकृतिक संसाधनों का अंतर -

बीकानेर और हनुमानगढ़ के बीच प्राकृतिक संसाधनों तथा भौगोलिक स्थितियों में अत्यंत स्पष्ट भिन्नता दिखाई देती है, जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण जीवन, कृषि उत्पादन और गरीबी की संरचना पर पड़ता है। बीकानेर का लगभग 70% भूभाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा केवल 150-250 मिमी के बीच रहती है, जो राष्ट्रीय औसत (लगभग 1100 मिमी) से कई गुना कम है। कम वर्षा और अत्यधिक तापमान (मई-जून में 48°C तक) के कारण मिट्टी में नमी नहीं ठहरती, जिससे खेती जोखिमपूर्ण और सीमित हो जाती है। बीकानेर के लगभग 60% ग्रामीण परिवार अभी भी वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर रहते हैं, जबकि भूजल का स्तर कई स्थानों पर 250-300 फुट तक नीचे है, जिससे सिंचाई के लिए बोरवेल भी महँगे और अस्थिर विकल्प बन जाते हैं।

इसके विपरीत हनुमानगढ़ की भौगोलिक स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल है। यहाँ औसत वर्षा

300-350 मिमी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिले का अधिकांश क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) से सिंचित होता है। IGNP के पहले चरण के बाद जिले के लगभग 70% कृषि क्षेत्र में सिंचाई की स्थायी सुविधा उपलब्ध हुई, जो बीकानेर की तुलना में अत्यंत बड़ा अंतर पैदा करती है। घग्गर नदी और नहरों के कारण यहाँ मिट्टी की उर्वरता भी बेहतर बनी रहती है। परिणामस्वरूप हनुमानगढ़ में प्रति हेक्टेयर औसत कृषि उत्पादन बीकानेर की तुलना में लगभग दो से तीन गुना अधिक पाया गया है।

इन प्राकृतिक संसाधनों के अंतर ने रोजगार और आय पर भी गहरा प्रभाव डाला है। हनुमानगढ़ में सिंचाई सुविधाओं के चलते ग्रामीण परिवारों को साल में दो से तीन फसलें उगाने का अवसर मिलता है, जबकि बीकानेर के अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्रों में किसान अक्सर एक फसल पर ही निर्भर रहते हैं। इसी वजह से हनुमानगढ़ की कृषि-आधारित ग्रामीण आय स्थिर और अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि बीकानेर में कृषि अस्थिरता के कारण लोग दिहाड़ी मजदूरी, पशुपालन और गैर-कृषि कार्यों पर निर्भर होते हैं।

इसी अंतर का परिणाम यह है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत हनुमानगढ़ में अपेक्षाकृत कम (लगभग 11-13%) और बीकानेर में अधिक (लगभग 18-20%) दिखाई देता है। इस प्रकार प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने न केवल कृषि उत्पादन को प्रभावित किया, बल्कि इन जिलों की संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक स्थिति को भी अलग-अलग दिशाओं में ढाला है।

कृषि अवसंरचना और इसकी गरीबी पर सीधी भूमिका -

हनुमानगढ़ में कृषि अवसंरचना का विकास विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) के विस्तार के बाद तेजी से हुआ, जिसने पूरे कृषि तंत्र को नया स्वरूप दिया। नहरों के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध होने के कारण यहाँ कृषि पूरी तरह जोखिममुक्त और बहुफसली संरचना में विकसित हुई। वर्ष 2023-24 के सरकारी आँकड़ों के अनुसार हनुमानगढ़ में कुल सिंचित क्षेत्र लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर है, जो जिले के कुल कृषि क्षेत्र का 70-75% भाग बनाता है। इस स्थायी जल उपलब्धता ने किसानों को गेहूँ, सरसों, चना,

कपास और सब्जियों जैसी नकदी फसलों की खेती करने में सक्षम बनाया। विशेष रूप से कपास, जो पानी की उपलब्धता पर निर्भर फसल है, का उत्पादन जिले में लगातार बढ़ता रहा है, वर्तमान अनुमान के अनुसार हनुमानगढ़ की कपास उत्पादकता राजस्थान औसत से लगभग 30-40% अधिक है। इसी प्रकार यहाँ गेहूँ की औसत उत्पादकता 45-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पाई गई है, जो बीकानेर की तुलना में लगभग दोगुनी है।

सिंचाई की स्थिरता ने केवल फसल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने का अवसर भी दिया। उर्वरकों, कीटनाशकों और उच्च गुणवत्ता के बीजों के नियमित उपयोग, खेतों की लेजर लेवलिंग, ड्रिप और स्प्रींकलर सिस्टम, तथा कृषि मशीनरी (ट्रैक्टर, हार्वेस्टर) का प्रसार हनुमानगढ़ में तेजी से देखने को मिलता है। जिले में स्थापित किसान सेवा केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), स्थानीय मंडियों और कृषि विपणन समितियाँ किसानों को प्रशिक्षण, बीज उपलब्धता और बाजार सूचना प्रदान कर रही हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ किसानों की औसत वार्षिक कृषि आय बीकानेर के किसानों की तुलना में 25-40% अधिक आँकी जाती है। नियमित कृषि आय ने गरीबी में उल्लेखनीय कमी लाई है और ग्रामीण परिवारों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास में निवेश करने की क्षमता दी है।

इसके विपरीत बीकानेर में कृषि अवसंरचना का स्वरूप पूरी तरह अलग है। यहाँ कुल कृषि क्षेत्र का केवल 25-30% ही सिंचित है, जबकि शेष क्षेत्र वर्षा आधारित है। औसत वर्षा 200 मिमी के आसपास होने से खेती अनिश्चित बनी रहती है, जिसके कारण कृषि आय स्थिर नहीं रहती। बोरवेलों पर निर्भरता बढ़ने से खेती का खर्च भी अधिक हो जाता है, और कई स्थानों पर भूजल की गुणवत्ता खारी होने के कारण उसका कृषि उपयोग भी सीमित है। इससे बीकानेर का किसान अक्सर केवल बाजरा, मूंगफली और चारे जैसी फसलों तक सिमट जाता है, जिनकी बाजार कीमत भी अधिक नहीं होती। जिले में औसत कृषि उत्पादकता हनुमानगढ़ की तुलना में 40-50% कम पाई गई है, जिसका सीधा प्रभाव ग्रामीण आय के स्तर पर पड़ता है।

कृषि से होने वाली यह आर्थिक अस्थिरता बीकानेर के ग्रामीण परिवारों को गैर-कृषि गतिविधियों जैसे दिहाड़ी मजदूरी, पशुपालन, ऊन उत्पादन, ट्रांसपोर्ट व छोटे व्यवसायों पर निर्भर बनने को मजबूर करती है। दिहाड़ी मजदूरी की मौसमी प्रकृति और कम आय का स्तर गरीबी को समाप्त करने के बजाय उसे स्थायी बनाता है। यही कारण है कि बीकानेर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी का प्रतिशत हनुमानगढ़ की तुलना में 5-7% अधिक दर्ज किया गया है।

स्पष्ट होता है कि हनुमानगढ़ में विकसित कृषि अवसंरचना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया है, जबकि बीकानेर की कमजोर और अनिश्चित कृषि व्यवस्था गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को धीमा कर रही है। इस प्रकार कृषि अवसंरचना का अंतर दोनों जिलों के ग्रामीण विकास और गरीबी के स्वरूप को बिल्कुल अलग दिशा में ले जाता है।

परिवहन और संपर्क अवसंरचना -

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन और संपर्क अवसंरचना केवल एक भौतिक सुविधा नहीं होती, बल्कि यह ग्रामीण जीवन की समग्र आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रगति का आधार बन जाती है। हनुमानगढ़ में सड़क नेटवर्क का विस्तार पिछले दो दशकों में विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना, कृषि आधारित व्यापार और सीमावर्ती सुरक्षा कारणों से तेजी से हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और राज्य वित्त आयोग के सहयोग से जिले के लगभग 92% गाँव पक्की सड़कों से जुड़े हुए हैं, जिससे कृषि उपज को समय पर मंडियों तक पहुँचाना, बच्चों का स्कूलों तक पहुँचाना और महिलाओं का स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुँचाना संभव हुआ। हनुमानगढ़-संगरिया, पीलीबंगा-रावतसर और नोहर-भादरा जैसे मार्गों पर बनी बेहतर सड़कें जिले के कृषि व्यापार को मजबूती प्रदान करती हैं। आँकड़े बताते हैं कि हनुमानगढ़ मंडी में कृषि उपज की औसत दैनिक आवक बीकानेर की तुलना में लगभग 30% अधिक है, जिसका एक प्रमुख कारण यही बेहतर परिवहन व्यवस्था है। सड़क संपर्क बढ़ने से निजी तथा सार्वजनिक परिवहन साधनों की उपलब्धता बढ़ी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु आवागमन भी सरल हुआ है और यह गरीबी उन्मूलन में प्रत्यक्ष योगदान देता है।

इसके विपरीत बीकानेर में हालाँकि पिछले वर्षों में सड़क निर्माण की गति बढ़ी है और जिला मुख्यालय तथा बड़े कस्बों से जुड़ाव काफी बेहतर हुआ है, लेकिन रेतिले भूभाग, धोरों और सीमावर्ती सुरक्षा क्षेत्रों के कारण कई गाँव अभी भी संपर्क की दृष्टि से कमजोर हैं। बीकानेर के

खाजूवाला, छतरगढ़, उनटला, 24 एमएल और कई अन्य दूरस्थ गाँव अब भी ढीली रेत वाले मार्गों या कच्ची सड़कों पर निर्भर रहते हैं, जहाँ वर्षा, आंधी या रेत जमाव के कारण परिवहन प्रभावित हो जाता है। राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास रिपोर्ट (2023) के अनुसार बीकानेर के केवल 78-80% गाँव ही पूरी तरह पक्की सड़कों से जुड़े हैं, जबकि शेष गाँवों में सड़कें मौसमी या कच्चे रूप में हैं। इस कमी का सीधा प्रभाव ग्रामीण शिक्षा पर पड़ता है—दूरस्थ स्कूलों तक पहुँच के अभाव में कई बच्चे विशेषकर लड़कियाँ माध्यमिक स्तर से आगे की पढ़ाई छोड़ देती हैं।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं में भी संपर्क अवसंरचना की कमी गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। बीकानेर के मरुस्थलीय इलाकों में कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक एम्बुलेंस सेवाओं की पहुँच बाधित रहती है, जबकि हनुमानगढ़ में सड़क नेटवर्क बेहतर होने के कारण गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो जाती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (NFHS-5) में पाया गया कि हनुमानगढ़ में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 91% है, जबकि बीकानेर के कुछ मरुस्थलीय ब्लॉकों में यह आँकड़ा 82-84% के आसपास है, जिसका प्रमुख कारण परिवहन सुविधा में अंतर है।

सड़क और परिवहन नेटवर्क रोजगार के अवसरों को भी प्रभावित करते हैं। अच्छी सड़कें ग्रामीण युवाओं को कस्बों और शहरों में नौकरी, उद्योग, सर्विस सेक्टर और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं। हनुमानगढ़ से सूरतगढ़, हिसार और श्रीगंगानगर जैसी शहरों तक नियमित आवागमन उपलब्ध है, जिससे बड़ी संख्या में युवा बाहर जाकर रोजगार प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत बीकानेर के उन क्षेत्रों में, जहाँ परिवहन सीमित है, रोजगार के अवसर भी सीमित रह जाते हैं, और लोग स्थानीय स्तर पर दिहाड़ी मजदूरी या पशुपालन जैसे पारंपरिक कार्यों पर निर्भर हो जाते हैं।

स्पष्ट है कि परिवहन एवं संपर्क अवसंरचना में दोनों जिलों के बीच का अंतर गरीबी उन्मूलन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। अच्छी सड़कें, नियमित परिवहन साधनों और सुगम संपर्क के कारण हनुमानगढ़ में ग्रामीण जीवन तुलनात्मक रूप से अधिक सुविधाजनक, गतिशील और आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है, जबकि बीकानेर के दूरस्थ मरुस्थलीय गाँवों में कमजोर संपर्क व्यवस्था अभी भी सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया को धीमा कर देती है।

शिक्षा अवसंरचना और मानव संसाधन विकास -

हनुमानगढ़ में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत ऊँचा है क्योंकि स्कूलों की संख्या अधिक, पहुँच सुगम और मध्याह्न भोजन योजनाएँ बेहतर लागू होती हैं। इसके चलते वहाँ साक्षरता दर, विशेषकर महिला साक्षरता, बीकानेर से बेहतर है। शिक्षित युवा आगे चलकर सरकारी सेवाओं, प्राइवेट सेक्टर और व्यवसायिक क्षेत्रों में अवसर प्राप्त करते हैं, जिससे परिवारों की गरीबी कम होती है।

बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की संख्या तो पर्याप्त है, लेकिन कई विद्यालयों में आधारभूत सुविधाएँ कमजोर हैं। लंबे दूरी के कारण लड़कियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है, जिससे भविष्य में उनकी आर्थिक भागीदारी सीमित हो जाती है।

स्वास्थ्य अवसंरचना और ग्रामीण सुरक्षा -

हनुमानगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रसूति सेवाएँ अपेक्षाकृत बेहतर हैं। नहर क्षेत्रों में बीमारियों का स्वरूप अलग होता है, परंतु स्वास्थ्य संस्थानों की उपलब्धता ने ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य खर्च को कम किया है, जो गरीबी उन्मूलन का महत्वपूर्ण कारक है।

बीकानेर के मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी से उत्पन्न बीमारियाँ, जल की गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ और पोषण की कमी अधिक पाई जाती हैं। स्वास्थ्य सुविधाएँ दूर होने के कारण ग्रामीण अक्सर असंगठित चिकित्सा पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ता है।

ऊर्जा, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार -

दोनों जिलों में बिजली की उपलब्धता में सुधार हुआ है, परंतु हनुमानगढ़ में कृषि कनेक्शन अधिक होने के कारण ग्रामीण रोजगार व्यापक रूप से बढ़ा है। डिजिटल कनेक्टिविटी और मोबाइल नेटवर्क ने सरकारी योजनाओं, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया, जिससे युवाओं में रोजगार के नए अवसर बने।

बीकानेर में भी ऊर्जा और संचार अवसंरचना बढ़ी है, लेकिन नेटवर्क व्यवधान और सुदूर गाँवों में सेवाओं की कमी के कारण डिजिटल अवसर समान रूप से विकसित नहीं हो सके।

महिलाओं की भूमिका और सामाजिक अवसररचना -

ग्रामीण अवसररचना केवल कृषि या परिवहन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक ढाँचे और विशेषकर महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डालती है। हनुमानगढ़ में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक भागीदारी पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है, जिसका प्रमुख कारण वहाँ उपलब्ध कृषि और सामाजिक अवसररचना है। जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के विस्तार के बाद कपास, गेहूँ, सरसों और सब्जियों के उत्पादन में निरंतर वृद्धि हुई, जिससे महिलाओं के लिए खेतों में कटाई-छँटाई, कपास चुनाई और सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों में रोजगार के स्थायी अवसर बने। सरकारी रिपोर्ट (2023) के अनुसार हनुमानगढ़ में ग्रामीण महिला श्रमबल भागीदारी दर 38-40% तक पहुँच गई है, जो बीकानेर की तुलना में लगभग 12% अधिक है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूहों (SHGs) ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिले में लगभग 8,500 SHGs सक्रिय हैं, जो माइक्रो-फाइनेंस, डेयरी, अचार-पापड़ उत्पादन, कटाई-बीनाई सेवाएँ, ब्यूटी सर्विसेज, और छोटे पैमाने के कृषि उपकरण किराये पर देने जैसे कार्य कर रही हैं। इन समूहों में शामिल महिलाओं की मासिक आय 3,000 से 8,000 रुपये तक बढ़ी है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिरता में बड़ा सुधार आता है।

कृषि आधारित डेयरी गतिविधियों में भी हनुमानगढ़ की महिलाएँ सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। जिले में प्रतिदिन लगभग 8-9 लाख लीटर दूध की खरीद सहकारी समितियों और निजी डेयरीयों के माध्यम से होती है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। इस आर्थिक गतिविधि ने महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाया है और उन्हें परिवार के आर्थिक निर्णयों में भाग लेने का अवसर दिया है। बेहतर सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाएँ और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएँ भी महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाती हैं—महिलाएँ अब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकारी योजनाओं तक सीधे पहुँच पा रही हैं। इसके विपरीत बीकानेर का सामाजिक और भौगोलिक वातावरण महिलाओं की आर्थिक भूमिका को प्रभावित करता है। यहाँ मरुस्थलीय भूभाग, जल-संकट और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था के कारण महिलाओं का कार्यभार अत्यधिक श्रमसाध्य होता है। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को प्रतिदिन औसतन 2-4 किलोमीटर तक पानी लाने जाना पड़ता है, जो उनके समय, स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रभावित करता है। जिले में महिला श्रमबल भागीदारी दर लगभग 26-28% है, जिसमें अधिकांश कार्य दिहाड़ी मजदूरी या पशुपालन से जुड़े होते हैं। चारा उत्पादन और पशुओं की देखभाल जैसे कार्य कठिन होते हैं और इनसे प्राप्त आय बहुत कम होती है, जिससे ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से स्थिर नहीं बन पाते। कुछ क्षेत्रों में SHGs सक्रिय हैं, परंतु उनकी संख्या हनुमानगढ़ की तुलना में कम है और उनका आर्थिक प्रभाव भी सीमित है।

बीकानेर में लड़कियों की शिक्षा भी परिवहन और सामाजिक बाधाओं के कारण प्रभावित होती है। दूरस्थ मरुस्थलीय गाँवों में माध्यमिक विद्यालयों की कमी और परिवहन की कमजोर स्थिति के कारण छात्राओं में स्कूल छोड़ने की दर हनुमानगढ़ की तुलना में अधिक पाई गई है। यह स्थिति महिला आर्थिक भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण को धीमा करती है।

इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि सामाजिक और आर्थिक अवसररचना, विशेषकर महिलाओं के लिए उपलब्ध सुविधाएँ, गरीबी उन्मूलन में निर्णायक कारक बन जाती हैं। जहाँ मजबूत अवसररचना है—वहाँ महिलाएँ सक्रिय, आर्थिक रूप से सक्षम और सामाजिक रूप से सशक्त हैं, जबकि कमजोर क्षेत्रों में गरीबी और सामाजिक सीमाएँ एक-दूसरे को मजबूत करती हैं।

निष्कर्ष -

बीकानेर और हनुमानगढ़ के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि ग्रामीण अवसररचना किसी भी क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति की रीढ़ होती है। हनुमानगढ़, जहाँ नहर सिंचाई, पक्की सड़कें, कृषि मंडियाँ, स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, महिला समूह और डिजिटल सेवाएँ अच्छी तरह विकसित हैं, वहाँ ग्रामीण गरीबी में पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय कमी आई है। स्थायी जल आपूर्ति और बहुफसली कृषि संरचना ने न केवल किसानों की आय बढ़ाई, बल्कि ग्रामीण रोजगार, महिला सहभागिता और सामाजिक विकास को भी मजबूती दी। परिवहन नेटवर्क और बाजारों से जुड़ाव ने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिरता बढ़ी।

इसके विपरीत बीकानेर में प्राकृतिक और भौगोलिक चुनौतियाँ अवसररचना विकास को धीमा

करती हैं। सीमित सिंचाई साधन, रेतीला भूभाग, कमजोर सड़क संपर्क और स्वास्थ्य-शिक्षा सेवाओं की अपर्याप्तता ग्रामीण गरीबी को बढ़ाती है। यहाँ के ग्रामीण परिवार अक्सर अनिश्चित कृषि, पशुपालन और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, जिससे आर्थिक अस्थिरता बनी रहती है। महिलाओं का श्रम अत्यधिक होता है, परंतु आय कम होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं बन पाती। तुलनात्मक रूप से स्पष्ट है कि जहाँ अवसररचना सुदृढ़ है वहाँ गरीबी कम है, और जहाँ अवसररचना कमजोर है वहाँ गरीबी एक स्थायी समस्या बन जाती है।

सुझाव -

1. बीकानेर में जल-संरक्षण और माइक्रो-इरिगेशन तकनीक का विस्तार

ट्रिप और स्प्रींकलर सिस्टम को सब्सिडी के साथ बढ़ावा दिया जाए ताकि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में भी बहुफसली खेती संभव हो सके।

छोटे तालाब, चेक डैम, परकोलेशन टैंक और रूफ-वॉटर हार्वेस्टिंग जैसी योजनाओं को गाँव स्तर पर लागू किया जाए।

2. दूरस्थ गाँवों में सड़क संपर्क मजबूत किया जाए

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधूरे मार्गों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए।

रेतीले क्षेत्रों में रेत-जमाव रोकने हेतु स्थायी अवरोध, ग्रीन बेल्ट और सड़क सुरक्षा ढाँचा विकसित किया जाए।

3. महिला शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार

प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लर्निंग सेंटर और कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएँ।

महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को कृषि-प्रसंस्करण, डेयरी, पॉल्ट्री, हस्तशिल्प और ई-कॉमर्स से जोड़ा जाए।

4. स्वास्थ्य अवसररचना का सुदृढ़ीकरण

बीकानेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-केंद्रों को 24x7 सेवाओं से सशक्त किया जाए।

एम्बुलेंस सेवाओं को मरुस्थलीय गाँवों तक सुनिश्चित किया जाए।

5. डिजिटल अवसररचना का विस्तार

सभी गाँवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधा और ई-गवर्नेंस सेवाएँ उपलब्ध करवाई जाएँ, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं तक सीधे पहुँच मिले।

6. हनुमानगढ़ मॉडल का उपयोग

बीकानेर में कृषि मंडियों का विस्तार, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, SHGs को वित्तीय सहायता और कृषि यांत्रिकीकरण को बढ़ावा देकर हनुमानगढ़ की सफल रणनीतियों को लागू किया जाए।

REFERENCES

- शर्मा, आर. (2018). ग्रामीण विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था. राजस्थान पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, पृ. 112-145।
- यादव, एस. (2020). मरुस्थलीय क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण. नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, पृ. 87-130।
- चौधरी, एम. एवं सिंह, ए. (2019). सिंचाई आधारित कृषि परिवर्तन. सूरज प्रकाशन, बीकानेर, पृ. 55-110।
- गुप्ता, डी. (2021). राजस्थान का ग्रामीण ढाँचा: चुनौतियाँ और संभावनाएँ. भारत प्रकाशन, जोधपुर, पृ. 60-95।
- ग्रामीण अवसररचना विकास रिपोर्ट (2022). ग्रामीण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 20-78।

6. कुमार, जे. (2017). भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण ढाँचा. वीर तेजा प्रकाशन, कोटा, पृ. 33-70।

7. सिंह, पी. (2021). राजस्थान का नहर विकास मॉडल. विकास प्रिंट्स, श्रीगंगानगर, पृ. 90-140।

8. मेघवाल, आर. (2018). थार मरुस्थल और आजीविका पैटर्न. चेतना प्रकाशन, बीकानेर, पृ. 44-102।

9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार सर्वेक्षण रिपोर्ट (NFHS-5), (2022). स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ. 10-65।